

>

Title: Regarding grievances of Accredited Social Health Activists (ASHA) in Uttar Pradesh -laid.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक महिलाओं को मातृत्व लाभ की योजना आशा बहुओं के माध्यम से केन्द्र सरकार पूरे देश में चला रखी है जिसके परिणाम स्वरूप मातृत्व एवं शिशु के मृत्यु दर में काफी कमी आयी है । पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा एवं बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही है । ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर के प्रसव से पूर्व कम से कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य करती है उसके उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाती है । आशा बहुओं द्वारा जननी शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद मात्र 600 रूपये प्रति केस अनुमन्य है वह भी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण उनके समक्ष काफी गंभीर संकट पैदा हो गया है जबकि आशा बहुओं के द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि की जगह पर 3000 रूपये प्रतिमाह मानदेय की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है । अपनी समस्याओं के निदान के लिए इन लोगों ने कई बार जन्तर मन्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया । जिसके कारण जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है । इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं ।'

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आशा बहुओं की समस्याओं एवं उनकी मांग का शीघ्र समाधान किया जाए ।

